

THE
PARLIAMENTARY DEBATES

OFFICIAL REPORT

IN THE HUNDRED AND FORTY-FIRST SESSION OF THE RAJYA SABHA

Commencing on the 23rd February, 1987/4th Phalguna, 1908 (Saka)

RAJYA SABHA

Monday, the 23rd February, 1987/4th
Phalguna, 1908 (Saka)

The House met at fifteen minutes past one of the clock, The Deputy Chairman in the Chair.

MEMBER SWORN

Shri Samar Mukherjee (West Bengal)

PRESIDENT'S ADDRESS— Laid on the table

SECRETARY-GENERAL: Madam, I beg to lay on the Table a copy of the President's Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 23rd February 1987. [Placed in Library. See No. LT-3657/87]

[Text of the President's Address in
Hindi]

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 1987 में संसद के इस पहले अधिवेशन में आपका स्वागत करने हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपके सामने जो बजट और विधान कार्य हैं उनको सफलता के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।

2. 1986 में हमने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी नीति में व्यापक तब्दीलियां की थीं, जिनके लाभ हमें मिले हैं। साथ ही, इसी वर्ष देश की एकता और अखण्डता के सामने बाहरी और अन्दरूनी चुनौतियां थीं, जिनके विरुद्ध राष्ट्र को जूझना पड़ा। हमारा धर्म-निरपेक्ष लोकतंत्र, साम्प्रदायिक और अलगाववादी ताकतों का साहस के साथ मुकाबला कर रहा है। लोकतंत्र, धर्म-निरपेक्षता और समाजवाद हमारे गणतन्त्र के आधार हैं। इन सिद्धान्तों में भारतीय जनता के विश्वास को कभी भी कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती।

3. पंजाब में लोकतंत्र, देश की एकता, प्रगति और धर्म-निरपेक्षता की पूरी शक्तियां राष्ट्र-विरोधी तत्वों को अलग-थलग करने और उन्हें मिटाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ये राष्ट्र-विरोधी तत्व विदेशी सूत्रों के इशारे व नियन्त्रण में काम कर रहे हैं। मुख्य मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला की लीडरशिप में पंजाब की राज्य सरकार और वहां के लोगों ने धर्म-निरपेक्ष प्रजातन्त्र के मूल्यों को कायम रखने में अपूर्व साहस दिखाया है। भारत की एकता और अखण्डता की रक्षा करने में पंजाब के लोग हमेशा आगे रहे हैं। आजादी की लड़ाई में उन्होंने ऐसी ऐतिहासिक भूमिका निभाई है जिसकी उनके दिल व दिमाग पर धर्म-निरपेक्षता और लोकतंत्र की कभी न मिटने वाली छाप पड़ी है। यही वजह है कि पंजाब की जनता ने धार्मिक भावनाओं को

खतरनाक तरीके से भड़का कर, लोकतंत्र प्रणाली की उभरने की घोर असंवैधानिक कोशिशों का डाट कर मुकाबला किया है। गुरु तानक देव ने जिस महान धर्म की स्थापना की थी, उस धर्म के पवित्र उमूलों और परम्पराओं का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करते हुए कुछ लोगों ने धार्मिक कार्यकर्ताओं और पवित्र धार्मिक स्थानों को, आतंक फैलाने और सरकारी तंत्र को तहस-नहस करने का साधन बनाया है। पंजाब का आज यही अहम मसला है। भारत की एकता और अखण्डता के शत्रु साम्प्रदायिक कटुता पैदा करना चाहते हैं और पंजाब में नफरत व हिंसा का वातावरण बनाना चाहते हैं। सरकार उनके नापाक इरादों को विफल करने के लिए काटवद्ध है। इन प्रतिद्रव्यावादी, फासिस्ट और राष्ट्र-विरोधी ताकतों पर काबू पाने के लिए जो धर्म के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है, सभी देश प्रेमी, धर्म-निरपेक्ष, लोकतंत्र और प्रगति में विश्वास रखने वाली ताकतों को एकजुट होकर भारत को मजबूत बनाना है। यह चुनौती हम सब के लिए है। इसे सबको स्वीकार करना होगा।

4. जैसे-जैसे हमारा राष्ट्र अपनी आजादी की 40वीं वर्षगांठ के नजदीक बढ़ रहा है, उसे धार्मिक कट्टरता और फिरकापरस्ती के खतरों का पूरा-पूरा अहसास हो रहा है। अप्रैल, 1948 में हमारी संविधान सभा (विधायी) ने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें सरकार से कहा गया था कि वह भारत के राजनैतिक जीवन में फिरकापरस्ती को खत्म करने के लिए कदम उठाए। इससे सिर्फ दो महीने पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। उस समय हमारे संविधान-निर्माताओं के दिमाग में दर्दनाक हत्याओं की याद भी ताजा थी। फिरकापरस्ती में देश की एकता को होने वाले खतरे उन्हें साफ तजर आ रहे थे। जैसे-जैसे हमने योजना के जरिए विकास के मार्ग पर कदम रखे, हम यह मान कर चले कि सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साम्प्रदायिक भावना अपने आप कमजोर हो जाएगी। लेकिन हमें अनुभव यह हुआ कि साम्प्रदायिक

और कट्टरपंथी ताकतों ने बाहरी ताकतों की मदद और शह पाकर, राष्ट्रवाद, धर्म-निरपेक्षवाद, लोकतंत्र और समाजवाद के बुनियादी मूल्यों को ही ललकारा है। फिरकापरस्ती और प्रतिद्रव्यावादियों के नापाक इरादों के विरोध में भारत की एकता और अखण्डता के पवित्र आदर्शों की रक्षा के लिए ही इन्दिरा गांधी जी शहीद हुईं। साफ दिखाई दे रही सामाजिक आर्थिक तरक्की के बावजूद, ये दूषित शक्तियाँ एक गहरे रोग की तरह जड़ पकड़े हुए हैं। हालात का तकाजा है कि स्थिति का फिर से जायजा लिया जाए और सरकार उस उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करना चाहती है। अनेकता में एकता हमारी मूल्यवान विरासत है, जिसकी रक्षा सभी प्रकार की फूट डालने वाली ताकतों का मुकाबला करके ही की जा सकती है।

5. आजादी की 40वीं सालगिरह और आधुनिक भारत के निर्माता जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनाने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं हो सकता कि हम अपने राष्ट्र से साम्प्रदायिकता के घातक रोग को मिटाने के लिए एकजुट होकर दृढ़ कार्रवाई करें। भारत के उप-राष्ट्रपति इस राष्ट्रीय समारोह समिति के अध्यक्ष हैं। धर्म-निरपेक्षता के आदर्शों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दिल में बिठाने के लिए यह समिति व्यापक कार्यक्रम बनाएगी।

6. एक ऐसे समय जब हमारी सरकार पंजाब में आतंकवादी कार्रवाइयों पर काबू पाने में लगी हुई थी, हमारी सीमाओं पर एक नया खतरा पैदा हुआ। जनवरी, 1987 में पाकिस्तान ने अपनी आक्रामक सेनाएं इस तरह तैनात कर दीं कि पंजाब और जम्मू-काश्मीर की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। जसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है हमारी सरकार पर ज्यादातर हमारे अर्थ-सैनिक बल तैनात हैं। इस स्थिति को देखते हुए, संसाधनों की रक्षा के लिए हमारी सरकार को अपने सशस्त्र सेनाओं को तैनात करना पड़ा। पाकिस्तानी सेनाओं की आगे की तरफ बढ़ती हुई हथकड़ी के कारण तनाव पैदा हो गया। प्रधान मंत्री ने दोनों

देशों की सरकारों की तुरन्त आपसी बातचीत की पहल की। दोनों सरकारों के बीच अभी हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में बातचीत के दौरान तनाव को कम करने के उपायों पर एक समझौता हुआ। पाकिस्तान रावी-चनाब क्षेत्र से आर्मी रिजर्व नार्थ को वापिस हटाने के लिए सहमत हो गया। आगे बातचीत इस्लामाबाद में होगी। भारत की नीति सभी देशों के साथ शान्ति और सहयोग रखने की है। अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के कई उपाय सरकार ने किए हैं। भारत अपनी प्रभुसत्ता और अखण्डता की रक्षा के लिए दृढ़ रहते हुए, इस बात के लिए हमेशा तैयार है कि दोनों देशों के बीच तनाव और अविश्वास के सभी कारणों को शिमला समझौते के तहत आपसी सहयोग की भावना से दूर किया जाए।

7. 1986 में मिजोरम समझौते के साथ, हमारे देश के उस खूबसूरत इलाके में दशकों से चली आ रही विद्रोह और संघर्ष की स्थिति समाप्त हो गई। इस समझौते के अनुसार, मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है और चुनाव कराए गए हैं। एक नई सरकार सत्ता में आई है।

8. अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने के लिए संसदीय अधिनियम के पारित हो जाने से, वहां के लोगों की पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करने की आकांक्षाएं पूरी हो गई हैं। नया राज्य 20 फरवरी, 1987 से बन गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों के इतिहास में एक नया अध्याय खुल गया है।

9. सरकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषायी मामलों के बारे में हमारे संविधान में जितने पवित्र आश्वासनों को शामिल किया गया है, उनका सही-सही पालन किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों की दशा सुधारने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी के 15-सूत्री कार्यक्रम के अमल की सूचना सावधानीपूर्वक रखी जा रही है।

1818 R S-2

10. मैंने अपने 20 फरवरी, 1986 के भाषण में, सरकार की 1986-87 और उससे आगे के प्राथमिकता के क्षेत्रों की रूपरेखा पेश की थी। नीति में मुख्यतः इन विषयों पर बल दिया गया था :—

- (i) नया बीस-सूत्री कार्यक्रम बनाना ;
- (ii) नई शिक्षा नीति तैयार करना ;
- (iii) ग्रामीण और शहरी निर्धनों की दशा सुधारने के लिए तकनीकी मिशन तैयार करना ;
- (iv) कृषि नीति को नई दिशा देना और हरित क्रांति को पूर्वी क्षेत्रों तक ले जाना ;
- (v) परिवार नियोजन की एक अधिक कारगर नीति ;
- (vi) औद्योगिक विकास को तेज करना ;
- (vii) निर्यात और पर्यटन का विकास ;
- (viii) प्रशासनिक तन्त्र में सुधार ; और
- (ix) चुनाव नियमों में परिवर्तन।

11. इन सभी क्षेत्रों में मेरी सरकार ने कार्रवाई की है और इसके अच्छे परिणाम निकलने शुरू हो गए हैं।

12. सन् 1986 के बीस-सूत्री कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु गरीबी को दूर करना है। नए कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

- (i) गरीबी दूर करने के कार्यक्रम जिनका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को बढ़ाना और उत्पादकता और उत्पादन में सुधार करना है ;
- (ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को न्याय मुहैया कराने के लिए कार्यक्रम ;
- (iii) आमदनी की असमानताओं को कम करना और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना ;

- (iv) महिलाओं को समान दर्जा दिलवाने के लिए आन्दोलन को मजबूत करना ;
- (v) युवकों के लिए नए अवसर पैदा करना ;
- (vi) सभी गांवों के लिए स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था ;
- (vii) पर्यावरण की सुरक्षा ;
- (viii) गांवों में ऊर्जा पहुंचाना ; और
- (ix) संवेदनशील प्रशासन ।

13. नई शिक्षा नीति बना ली गई है। यह गरीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई का एक कारगर हथियार है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य गरीबों और शोषितों तक पहुंचकर उनके हाथों में ऐसे साधन देना है जिससे वे अपने भाग्य के खुद मालिक बन सकें। आपरेशन ब्लैकबोर्ड, गैर-श्रीपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और नवोदय विद्यालय जैसे कार्यक्रम शिक्षा में गुणवत्तात्मक परिवर्तन लाएंगे। वे समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को सीधे सहायता पहुंचाएंगे। नई शिक्षा नीति से कौमी एकता भी मजबूत होगी। हमने अपने सभी नागरिकों में इस बात का एहसास जगाने की अहमियत पर जोर दिया है कि भारत की विरासत में हम सबकी शिरकत है। इस काम को नए-स्थापित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों ने उत्साहपूर्वक शुरू कर दिया है। उन्होंने राजधानी में अपना उत्सव और पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में हमारी संस्कृति के नए तरीके के उत्सव आयोजित किए हैं।

14. जिन क्षेत्रों में पांच तकनीकी मिशन कायम किए गए हैं वे इस प्रकार हैं :—

- (i) सभी गांवों के लिए पीने का पानी,
- (ii) निरक्षरता को दूर करना ;

- (iii) सभी बच्चों का रोगों से प्रतिरक्षण;
- (iv) तिलहनों और खाद्य-तेलों का उत्पादन ;
- (v) बेहतर संचार व्यवस्था ।

सरकार मिशनों के लिए एक कारगर प्रबन्ध और मानीटोरिंग प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर विचार कर रही है। यहां मुख्य उद्देश्य लोगों को मिशनों से संबंधित क्रियाकलापों में शामिल करना है ताकि वे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की संभावना को कार्यरूप दे सकें।

15. कृषि सम्बन्धी नीति में और सुधार का कार्य सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। पूर्वी अंचल में उत्पादकता में वृद्धि ने सरकार की नीति को सही साबित कर दिया है। हमारे भू-संसाधनों के बहुत बड़े भाग में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने और स्थिर करने के लिए चालू वर्ष में 16 बड़े वर्षा सिंचित/सूखी खेती करने वाले राज्यों में वाटर शैड विकास के द्वारा वर्षा सिंचित कृषि का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया है। आवश्यक प्रोटिन वाली दालों की फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 1986-87 में 50 करोड़ रुपये की लागत से एक राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना आरम्भ की गयी है।

16. हमने एक नई परिवार नियोजन नीति तैयार की है जिसके अन्तर्गत दो बच्चों के मानदण्ड को स्वेच्छा से स्वीकार करने पर अधिक जोर दिया गया है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य रक्षा, आहार और शिक्षा कार्यक्रमों के साथ समन्वित होगा। सरकार ने निश्चय किया है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने में स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रमुख भूमिका निभाना चाहिए।

17. उद्योग के क्षेत्र में कार्यकुशलता और आधुनिकीकरण पर दिये गये विशेष जोर के परिणाम सामने आने लगे हैं। औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है।

18. प्राथमिक वस्तुओं और तैयार समान दोनों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक समन्वित नीति के अनुसार ठोस प्रयास किए गए हैं। हमारी नीति में उत्पादन को संवर्धन क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। निर्यात हेतु उत्पादन के लिए आधुनिक पूंजीगत माल के आयात पर शुल्क में छूट दी गई है। जिन क्षेत्रों पर हम इस समय जोर दे रहे हैं, वहां मौजूदा तकनीक उपयोग में लाई जा रही है। निर्यात को और अधिक बढ़ावा देने के इरादे से महत्वपूर्ण वित्तीय और आर्थिक कदम उठाए गए हैं, जैसे नई नकद मुद्रावजा योजना, शुल्क वापसी प्रणाली, 38 घोषित विषयों में "मोडवेट" की व्यवस्था, निर्यात के लिए लाभ में छूट, निर्यात के लिए जहाज में लदान-पूर्व तथा लदान-बाद ऋण की व्याज-दरों में भारी कमी तथा नई कम्प्यूटर साफ्टवेयर नीति।

19. हमारी प्रशासनिक पद्धति में सुधार की प्रक्रिया की गति तेज हुई है। बदलती परिस्थितियों में ठोस नतीजों पर जोर, सामाजिक जिम्मेदारी और एक नई कार्य पद्धति का प्रशासन में शामिल करना है। इन अस्थाओं के प्रति हमारे लोक-सेवकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। सरकार, कार्य बल के सभी वर्गों के सहयोग से सरकारी प्रबन्ध में गुणवत्ता के एतबार में सुधार लाने के कार्य को आगे बढ़ाने का पक्का इरादा रखती है।

20. हमारी निर्वाचन पद्धति का बुनियादी ढांचा समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इसके कारण ही संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाच और स्वच्छ चुनाव सम्पन्न हुए हैं और इसी कारण सारी दुनिया में इसको मान्यता तथा प्रशंसा मिली है। मुख्य चुनाव आयुक्त की 1986 की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कुछ सुझाव तय किये हैं जिन पर विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ विचार-विमर्श होता है, तथा उन्हें आम सहस के लिए भी खोला जाना है। जैसाकि पहले किया गया था, ऐसे विचार-विमर्श में उत्पन्न सर्वसम्मति के आधार पर आवश्यक कानून बनाये जायेंगे।

21. वर्ष 1986 राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर असर डालने वाले सार्थक कानूनों के लिए याद किया जाएगा। एक कठोर और व्यापक पर्यावरण संरक्षण कानून बनाया गया है। पर्यावरण के प्रति हमारे आत्मचिन्तन को जागृत करने में जितनी अहम भूमिका श्रीमती इन्दिरा गांधी ने निभाई उतनी और किसी ने नहीं। उनकी याद में सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में यह कानून 19 नवम्बर, 1986 से लागू हो गया है।

उपभोक्ताओं के अधिकारों को कानून की पुस्तक में स्थान दिया गया है।

महिलाओं के स्तर को सुधारने के लिए प्रगतिशील कानून पास किए गए हैं।

व्यापारिक उद्देश्य से अनैतिक व्याभिचार के शिकार सभी व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिए महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक व्याभिचार दमन कानून 1956 में संशोधन किया गया है। बच्चों और नाबालिगों की व्याभिचार-कमाई पर जीवन चलाने वालों के लिए और अधिक कठोर सजा निर्धारित की गई है।

दहेज-विरोधी कानून में संशोधन किया गया, जिसके तहत अब यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी कि दहेज की कोई मांग नहीं थी, दहेज लेने वाले या दहेज लेने के लिए उकसाने वाले की है। इस कानून के तहत जुर्माने के लिए जमानत नहीं हो सकती है।

महिलाओं का अश्लिष्ट प्रदर्शन (निरोधक) कानून पास कर लिया गया है जिसके अन्तर्गत किसी महिला की आकृति, उसके नख-शिख या शरीर के ऐसे अभद्र असम्मानपूर्ण प्रदर्शन को, जिससे महिलाओं की बेइज्जती हो, दण्डनीय बनाया गया है।

इन कानूनों का एक सार्थक पहलू यह है कि कोई भी नागरिक इनके तहत न्यायालय में जा सकता है। इन व्यापक कानूनों को लागू करने में जनहित-प्रेमी जागरूक नागरिकों का सहयोग बहुत अहमियत रखता है।

22. अब मैं अर्थ व्यवस्था की प्रमुख प्रवृत्तियों पर बात करूंगा।

23. मानसून का अच्छा रुख न होने के बावजूद, वर्ष 1986-87 में कुल राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस प्रकार लगातार दूसरे वर्ष में भी सातवीं योजना के वृद्धि-दर लक्ष्य पूरे हो जाएंगे।

24. लगातार तीसरे वर्ष पर्याप्त वर्षा न होने के बावजूद खाद्यान्नों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कुछ वृद्धि होगी। सरकार इस बात से चिन्तित है कि हालांकि कृषि उत्पादन में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है पर उत्पादन के एक ऊंचे स्तर पर रुकने के आसार हैं। लगातार तीन वर्षों तक बहुत कम वर्षा होने के कारण भी ऐसा हुआ है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए मूलभूत नीति काफी सुदृढ़ है। सिंचाई की सम्भावनाओं को बढ़ाने और बीजों की ज्यादा पैदावार देने वाली किस्मों के इस्तेमाल को लोक-प्रिय बनाने वाली परियोजनाओं और कार्यक्रमों को जोरदार ढंग से लागू करने से, विश्वास है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के वृद्धि-दर लक्ष्यों को हासिल कर लिया जाएगा। सरकार ने देश में तिलहनो के उत्पादन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी काम उठाये हैं।

25. बुनियादी औद्योगिक ढांचे की प्रगति वर्ष 1985-86 और 1986-87 में बहुत अच्छी रही है। पिछले दो वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि दरें बिजली में 9.5 प्रतिशत, कोयले में 6 प्रतिशत, बाजार-योग्य इस्पात में 7.7 प्रतिशत, होट मैटल धातु में 6.8 प्रतिशत, रेल भाड़े में 8 प्रतिशत और उर्वरकों में 16.5 प्रतिशत होने की आशा है। इस बुनियादी औद्योगिक ढांचे की खासियत यह है कि वार्षिक कार्य निष्पादन में हर तिमाही में लगातार सुधार हुआ है। कई क्षेत्रों में तो किसी एक तिमाही का न्यूनतम उत्पादन, पिछले वर्ष की किसी भी तिमाही के उच्चतम उत्पादन से भी अधिक रहा है। बुनियादी ढांचा अब पूंजीनिवेशों का कुशल उपयोग करने लगा है।

26. पुराने सूचकांक के मुकाबले व्यापार और अधिक नुमाइंदगी वाले औद्योगिक उत्पादन के नए संशोधित सूचकांक आधार वर्ष (1980-81-100) में संतोषजनक औद्योगिक वृद्धि का संकेत मिलता है। वर्ष 1985-86 में औद्योगिक उत्पादन 8.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा। वर्ष 1986-87 में वृद्धि दर सात आठ प्रतिशत होने का अनुमान है। पिछले दो वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स समान में प्रभावशाली वृद्धि रही है जिस की दर करीब 40 प्रतिशत प्रति वर्ष रही है। हमारे आर्थिक विकास में सरकारी क्षेत्र के उद्यम अहम भूमिका निभाते रहे हैं। वर्ष 1985-86 के अन्त में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का कुल पूंजीनिवेश 50,341 करोड़ रुपये था जो वर्ष 1984-85 की तुलना में 14,947 करोड़ रुपये अधिक है। केन्द्रीय सरकार के उद्यमों की आर्थिक उपलब्धि उत्साहजनक रही है। सरकारी उद्यमों की स्वायत्तता को मजबूत करने और उन्हें परिणामों के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं।

27. खाद्यान्नों का सरकारी भण्डार उच्च स्तर पर रहा है और दिसम्बर, 1986 में यह 230 लाख टन था। इसके कारण ही सरकार जनता में वितरण करने के लिए राज्यों को और अधिक चावल और गेहूं दे सकी, समन्वित आदिवासी विकास परियोजनाओं और ग्रामीण कार्यक्रमों को रियायती दरों पर गेहूं दे सकी तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण मजदूर रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के लिए और अधिक आवंटन कर सकी। खाद्यान्नों का अच्छा भण्डार होने के कारण ही सरकार काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए सूखा-ग्रस्त राज्यों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न दे सकी।

28. गन्ना और चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नीति को और अधिक अनुकूल बनाया गया है। नई द्विवार्षिक चीनी नीति का उद्देश्य गन्ना पैदा करने वाले किसानों को अधिक लाभदायक मूल्य उपलब्ध कराना है। इसके अधीन एक

वर्ष पूर्व ही कानूनी न्यूनतम मूल्य घोषित करने से भी माहौल स्थिर हुआ है। इस नीति के परिणामस्वरूप वर्ष 1985-86 में चीनी का उत्पादन करीब दस लाख टन बढ़ा है और वर्ष 1986-87 के दौरान इसमें और वृद्धि होने की आशा है। इसी वजह से सरकार चीनी का आयात कम करने में सफल हुई है।

29. तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीकी मिशन ने काम करना आरम्भ कर दिया है। वर्ष 1989-90 में तिलहनों की पैदावार को 180 लाख टन तक पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है। 1989-90 के दौरान इस कार्यक्रम पर 170 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। प्रतिकूल मौसम के कारण वृष्टि क्षेत्रफल में 3 प्रतिशत की कमी आ जाने के बावजूद वर्ष 1985 की तुलना में वर्ष 1986 की खरीफ फसल में तिलहनों की उत्पादकता में 10 प्रतिशत और उत्पादन में 7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। देसी पैदावार को प्रोत्साहन देने के लिए खाद्य तेलों का आयात कम किया गया। वर्ष 1985-86 में आयात में लागत के हिसाब से 55 प्रतिशत और परिमाण के हिसाब से 15 प्रतिशत की कमी की गयी। गौण तिलहनों और धान की भूसी से अधिक मात्रा में तेल निकालने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिए गये।

30. वर्ष 1986-87 में गरीबी के खिलाफ कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) और रोजगार कार्यक्रम गरीबी के खिलाफ अभियान के सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग हैं। वर्ष 1986-87 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 543.83 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई। इसकी तुलना वर्ष 1984-85 में दिए गए 207.7 करोड़ रुपये और वर्ष 1985-86 में दिये गये 205.9 करोड़ रुपये में की जा सकती है। दिसम्बर, 1986 के अन्त तक 20.7 लाख परिवारों को सहायता दी जा चुकी थी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जो नई विशेषताएं लाई गई हैं, वे हैं—प्रति परिवार पूंजीनिवेश का उच्चतर स्तर, अगले

और पिछले सम्पर्कों का प्रावधान, लाभ-प्राप्तकर्ताओं के प्रशिक्षण पर बल, स्वैच्छिक संस्थाओं की शिरकत, समवर्ती मूल्यांकन का प्रावधान तथा महिलाओं को और अधिक सहायता देना। इन सभी कार्यक्रमों में अत्यन्त गरीब लोगों एवं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को अधिक से अधिक सहायता देने पर मूल रूप से बल दिया गया है।

31. 1986-87 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को सुदृढ़ किया गया। इससे कुल 5500 लाख मनुष्य-दिवस रोजगार पैदा होने की आशा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए परिव्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1984-85 में 230 करोड़ रुपये और 1985-86 में 337.21 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबल केन्द्र द्वारा 1986-87 में कुल 479.75 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन, जिसके लिए सम्पूर्ण धन-व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जाती है, 1986-87 के लिए 731.10 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया जिसकी तुलना 1984-85 में उपलब्ध कराये गए 400 करोड़ रुपये और 1985-86 में 606.33 करोड़ रुपये से की जा सकती है।

32. 1986 के 20-सूत्री कार्यक्रम में सभी गांवों में पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराए जाने पर बल दिया गया है। 1986-87 में, केन्द्रीय और राज्य योजनाओं में पेय जल कार्यक्रम के लिए कुल 794.05 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। इस कार्यक्रम के तहत 40,000 गांवों के आ जाने की आशा है जो 35,930 गांवों के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जलपूर्ति की व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

33. 1986-87 में वार्षिक योजना के परिव्यय में काफी वृद्धि की गई थी। हमारी योजना के इतिहास में पहली

बार, योजना-अवधि के पहले दो वर्षों में पंचवर्षीय योजना का 40 प्रतिशत धन वास्तविक रूप से उपलब्ध करा दिया गया। संसाधनों का आवंटन करने में गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों को और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुदृढ़ करने को उच्च प्राथमिकता दी गई। गरीबी-विरोधी मुख्य कार्यक्रमों के लिए परिव्यय में 65 प्रतिशत की भारी वृद्धि की गई। कृषि, ग्रामीण विकास और सिंचाई के लिए परिव्यय में लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि की गई। शिक्षा संबंधी परिव्यय में लगभग 60 प्रतिशत वृद्धि की गई। 1986-87 की केन्द्रीय योजना में 22,300 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया था जिसमें पिछले वर्ष के परिव्यय के मुकाबले 20.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। योजना में वास्तव में ज्यादा धन राशि, 23,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। भारत के विकास में मूलभूत भूमिका निभाने के सरकार के दृढ़ संकल्प का इससे बेहतर और कोई उदाहरण नहीं हो सकता।

34. सरकार ने लम्बी अवधि की वित्तीय नीति में निहित बुनियादी प्रस्तावों पर अमल करने के लिए उपाय किए हैं। कर-ढाँचे में सुधार करके उसे सरल बनाया जा रहा है। कर की अदायगी को बढ़ाने के लिए बेहतर प्रशासन और प्रवर्तन के द्वारा विकास के लिए संसाधन जुटाने पर अधिक जोर दिया गया है, बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्थायी वित्तीय माहौल पैदा किया जा रहा है, और वित्तीय नीति के संबंध में ज्यादा खुला हुआ दृष्टिकोण अपनाया गया है।

35. केन्द्रीय सरकार के राजस्व, जिसमें 1985-86 में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अप्रैल-दिसम्बर 1986 में 17 प्रतिशत से अधिक और वृद्धि हुई है। वैयक्तिक आयकर की वसूलियों में 1985-86 में 30 प्रतिशत की शानदार वृद्धि हुई है। अप्रैल-दिसम्बर 1986 में इनमें 16 प्रतिशत और वृद्धि हुई है। केन्द्रीय राजस्व में लगातार वृद्धि ने करों की तर्कसंगत दरों और कर संबंधी कानूनों की सख्ती से लागू करने के प्रति सरकार के मौलिक दृष्टिकोण को सही ठहराया है।

36. निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से नीतियों और कार्यक्रमों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए मंत्रिमंडल की एक निर्यात संबंधी समिति का गठन किया गया। अप्रैल-नवम्बर, 1986 में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 17.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। उसी अवधि में निर्यात में केवल 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप, व्यापार-घाटे में काफी कमी आई है। फिर भी, हम संतुष्ट नहीं बैठ सकते। आत्म-निर्भर होने और पूरी तरह से स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए अधिक कोशिशें करने की जरूरत है।

37. चालू वर्ष में हमने दस लाख विदेशी पर्यटकों के आगमन का लक्ष्य पार कर लिया है। 1985-86 के दौरान 1300 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की आय के मुकाबले, पर्यटन से लगभग 1600 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है।

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए घरेलू पर्यटन की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार मार्गीय सुविधायें, वन्य प्राणी विहारों, ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रमों और सस्ते पर्यटक आवासों के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

38. जबकि संसाधन जुटाने के मामले में शानदार नतीजे हासिल हुए हैं सरकारी खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए इसी तरह की कोशिश करनी होगी। सामाजिक न्याय के साथ-साथ विकास की आवश्यकता, गैर-उत्पादक खर्च पर रोक लगाने की ओर गंभीरता से ध्यान देने पर मजबूर करती है।

39. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक चिंता का विषय है। यह जरूर है कि यदि कीमतों को थोक मूल्य सूचकांक की दृष्टि से देखें तो मुद्रा के फैलाव को तर्कसंगत सीमा के भीतर रखा गया है। सरकार हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के फैलाव की प्रवृत्ति को प्रभावहीन करने की नीतियों का अनुसरण करती रहेगी।

40. पिछले दो वर्षों के दौरान औद्योगिक संशोधनों में सुधार की सही प्रवृत्ति देखने में आई है। हड़तालों और तालाबंदियों की संख्या 1984 में 2094 से घटकर 1985 में 1716 और 1986 में

(जनवरी से अक्तूबर तक) 1234 हो गई। औद्योगिक विवादों के कारण होने वाली मनुष्य-दिवसों की हानि में कमी आई है। 1984 में 560.3 लाख मनुष्य-दिवसों की क्षति के मुकाबले 1985 में 293.7 लाख मनुष्य-दिवसों और 1986 में (जनवरी से अक्तूबर तक) 194.1 लाख मनुष्य-दिवसों की क्षति हुई है। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं कि असंगठित श्रमिकों को उनके जायज फायदे मिल सकें।

पिछले दो वर्षों में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए औद्योगिक श्रमिकों ने प्रशसनीय योगदान दिया है। सरकार उनके हित की रक्षा करने और औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है।

41. सरकार न्याय पर आधारित विश्व समाज का निर्माण करने में शांति, निरस्त्रीकरण, विकास और सभी देशों के साथ सहयोग की अपनी गुटनिरपेक्ष विदेश नीति के उद्देश्यों के लिए कोशिश कर रही है।

42. पांच महाद्वीपों के छह राष्ट्रों की पहल से, जिसमें अर्जेंटीना, यूनान, भारत, मेक्सिको, स्वीडन और तंजानिया शामिल हैं, परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए लगातार और भारी कोशिशों के पक्ष में संसार भर में लोकमत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। रेकजेविक में परमाणु अस्त्रों की होड़ को खत्म करने के लिए प्रभावकारी प्रस्ताव रखे गए। दुर्भाग्य की बात है कि उन पर कोई समझौता नहीं हो सका। हमने अमरीका और सोवियत संघ दोनों से शांति और परमाणु हथियारों से मुक्त समाज की स्थापना के लिए मानवजाति की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखने का आग्रह किया है।

43. हरारे गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत ने आन्दोलन की अध्यक्षता जिम्बाबवे को सौंप दी। सम्मेलन में गुट-निरपेक्षता को मजबूत करने और इस आन्दोलन के मूल उद्देश्यों को और पक्का करने में हमारे देश की भूमिका की प्रशंसा

की गई। सम्मेलन ने, रंगभेद की नीति के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने और अग्रिम पंक्ति के राष्ट्रों के प्रयासों को समर्थन देने के लिए नवगठित अफ्रीका कोष समिति की अध्यक्षता हमारे प्रधान मंत्री को सौंप दी। 24-25 जनवरी, 1987 को दिल्ली में हुए अफ्रीका कोष शिखर सम्मेलन ने हरारे की धारणा को ठोस आकार दिया है। सरकार यह मानती है कि व्यापक अनिवार्य प्रतिबंध ही दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार को रक्तपात रोकने और विवेक की आवाज सुनने पर मजबूर कर सकते हैं। जो सरकार अपने व्यापारिक और आर्थिक संबंधों के कारण दक्षिण अफ्रीका पर दबाव डालने की स्थिति में हैं उन्हें व्यापक अनिवार्य प्रतिबंधों के जरिए अपना दबाव तेज करना होगा।

44. हमारे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की भारत की नीति के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। भारत की अध्यक्षता में नवम्बर, 1986 में बंगलौर में हुए सफल सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ) सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग के लाभों को दर्शाया गया है। अब सार्क का एक स्थायी सचिवालय काठमांडू में स्थापित किया गया है। सार्क सहयोग के कार्यक्रम के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाया गया है जिनमें नशीले पदार्थों के व्यापार पर नियंत्रण, बाल कल्याण, प्रसारण, पर्यटन और वजीफे शामिल हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने सार्क बैठक के अवसर का उपयोगी द्विपक्षीय विचार-विमर्श के लिए लाभ उठाया है।

45. पाकिस्तान द्वारा हमारी सीमाओं पर अपनी फौजें तैनात किए जाने से हुई बाधा के बावजूद, पाकिस्तान के साथ सहयोग का आधार बनाने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। संबंधों को सामान्य बनाने की राह में जो मुख्य बाधाएँ हैं, वे हैं पाकिस्तान द्वारा गुप्त रूप से परमाणु हथियारों की क्षमता प्राप्त करने का प्रयास, उसका शस्त्र कार्यक्रम, जिसका हमारे सुरक्षा के वातावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, और पंजाब में राष्ट्र-विरोधी तथा अलगाववादी तत्वों को इसका समर्थन।

46. यह दुर्भाग्य की बात है कि श्रीलंका के साथ बंगलौर में हमारे द्विपक्षीय विचार-विमर्श और वाद में दिसम्बर, 1986 में उच्चस्तरीय परामर्श से उत्पन्न आशाओं को ठेस पहुंची है। श्रीलंका सरकार के 19 दिसम्बर, 1986 के अपने फार्मूले के बारे में उनके दुलमुल रवैये के कारण बातचीत की प्रक्रिया में बाधा पहुंची है। श्रीलंका की सुरक्षा सेनाओं द्वारा चलाए गए भारी सैनिक अभियानों और जाफना क्षेत्र की आर्थिक नाकाबंदी के कारण और जटिलताएं पैदा हुई हैं। श्रीलंका की तमिल असैनिक आबादी को जिन कठिनाइयों और तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और जान से हाथ धोना पड़ रहा है उसके प्रति हमारी गहरी चिन्ता है। श्रीलंका के जातीय मसले को केवल राजनीतिक बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है।

47. मेरी सरकार चीन के साथ सीमा प्रश्नों के न्याय संगत और शांतिपूर्ण हल के लिए लगातार कोशिश कर रही है। हमारे सम्बन्धों को पूरी तरह से सामान्य बनाने में यह प्रश्न महत्वपूर्ण घटना चिन्ता का कारण बनी हुई है। सीमा प्रश्न पर हमारी स्थिति को सभी अच्छी तरह जानते हैं। इस प्रश्न पर चीन के साथ हमारी बातचीत जारी है।

48. हम फिलिस्तीनी जनता के अभेद्य अधिकारों की हिमायत करते हैं। हम दक्षिण अफ्रीका के लोगों के मुक्ति संघर्ष का समर्थन करते हैं। हम ईरान और इराक के बीच भाई-भाई की लड़ाई का जल्द खात्मा चाहते हैं। हम मध्य अमरीका में संकट के शांतिपूर्ण स्थायी हल के लिए कांटाडोरा ग्रुप के प्रयासों का समर्थन करते हैं। हम अफगानिस्तान के मामले में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की पहल का भी समर्थन करते हैं। अफगानिस्तान के बारे में शेष मुद्दों पर लचीली प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि अफगानिस्तान को एक ऐसे स्वतंत्र, गुटनिर्पेक्ष देश का दर्जा मुकम्मल करने की परिस्थितियां शीघ्र बनेंगी और उनमें कोई बाहरी ताकतों से दखलंदाजी और प्रवेश नहीं होगा।

49. पिछले साल मैंने नेपाल, यूनान, पोलैंड और यूगोस्लाविया की सद्भावना यात्रायें की। उप-राष्ट्रपति फ्रांस और बोत्सवाना गए। प्रधान मंत्री ने मालदीव, जाम्बिया, जिम्बाबवे, अंगोला, तंजानिया, मारिशस, मैक्सिको, इन्डोनेशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और थाइलैंड की द्विपक्षीय यात्रायें की। प्रधान मंत्री ने लंदन में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की समीक्षात्मक बैठक, पांच महाद्वीपों के छह राष्ट्रों को शांति के लिए पहल से संबंधित शिखर बैठक में इससतपा में और हरारे में आठवें गुट-निर्पेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लिया और इसके अलावा उन्होंने स्वीडन के स्वर्गीय प्रधान मंत्री ओलोफ पाल्मे के अन्तिम संस्कार में शामिल होने के लिए स्वीडन की भी यात्रा की।

50. हमें यूनान के प्रधान मंत्री, कोरिया गणराज्य के प्रधान मंत्री, तुर्की के प्रधान मंत्री, सेशल्स के राष्ट्रपति, जर्मन जनवादी गणतंत्र के चांसलर, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, स्वापों के अध्यक्ष, बंगलादेश के राष्ट्रपति, यूगोस्लाविया के प्रधान मंत्री, निकारगुआ के राष्ट्रपति, जाम्बिया के प्रधान मंत्री, जार्डन के शाह, डेनमार्क के प्रधान मंत्री, पेरू के राष्ट्रपति, मलेशिया के प्रधान मंत्री और फिनलैंड के राष्ट्रपति की मेजबानी करने का मौका मिला। पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ यमन के तत्कालीन प्रधान मंत्री और अब राष्ट्रपति तथा इटली के प्रधान मंत्री अपनी यात्राओं के दौरान भारत में रुके। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया-उल हक गैर सरकारी यात्रा पर आये।

51. इन द्विपक्षीय यात्राओं से इन देशों के साथ हमारे मैत्री संबंध मजबूत हुए हैं। आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए बहुत से करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

52. भारत-सोवियत संघ के बीच 40 वर्षों के सहयोग से उभरे घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों के संदर्भ में, सी० पी० एस० यु०

के जनरल सैक्रेटरी, श्री गोरबाचोव की यात्रा एक महत्वपूर्ण घटना थी। श्री गोरबाचोव और हमारे प्रधान मंत्री ने दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर किए जिससे अहिंसा, न्याय तथा समता पर आधारित अन्तराष्ट्रीय संबंधों के लिए एक बिल्कुल नई संचरना उपलब्ध हुई है। इसका मानवता का कठिन समस्याओं के अनुरूप नए दृष्टिकोण और मूल्यों की स्थापना करने में विश्वव्यापी प्रभाव पड़ेगा।

53. सरकार की नीति का जोर समाज के आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के कल्याण में सुधार लाने पर है। पिछले दो सालों में लागू की गई नीतियों और कार्यक्रमों का ज्यादा जोर भूमिहीन कृषि मजदूरों, छोटे मामूली किसानों, कारीगरों, और दस्तकारों, हथकरघा बुनकरों, महिलाओं और बच्चों, शहरी गरीबों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की सहायता करने पर रहा है। हमारी विकास नीति में सामाजिक न्याय पर जोर दिया जाता रहा है। हम इस सर्वोपरि उद्देश्य पर कायम रहेंगे।

54. बहुत-सी समस्याओं के बावजूद, लोगों में एक मजबूत और खुशहाल भारत बनाने की अपनी क्षमता में पूरा विश्वास है। यह विश्वास हमारी शानदार उपलब्धियों का नतीजा है। भारत स्थिरता तथा प्रगति का प्रतीक बनकर मजबूती से खड़ा है। बुनियादी मूल्यों के प्रति हमारी वचनबद्धता और अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के हमारे दृढ़ संकल्प ने हमें अन्तः सिरे जंचा उठाकर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान की है। हमें अभी बहुत कुछ करना है। जनता के सहयोग और असीम उत्साह की मदद से मेरी सरकार देश को अपने चुने हुए रास्ते पर और आगे ले जाएगी।

55. हमारे कार्य मुख्य रूप से मूलभूत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सम्बद्धता को मजबूत बनाया जाएगा।

साम्प्रदायिकता का दृढ़ता से मुकाबला किया जाएगा। गरीबी के खिलाफ कार्यक्रम को पूरी शक्ति से लागू किया जाएगा। अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्रों को मजबूत बनाया जाएगा और उनमें विस्तार किया जाएगा ताकि विकास कार्य में हम आत्म निर्भर हों। युवकों की शक्ति और स्फूर्ति को राष्ट्र निर्माण में लगावेंगे। आजादी की लड़ाई में हमारी कुर्बानी की जो भावना रही था हमें उसे फिर से जागृत करना है। ताकि हम मौजूदा चुनौतियों का सामना कर सकें। हमारे दिलों में राष्ट्र निर्माण का जज्बा होना चाहिए। इन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।

जय हिन्द।

[Text of the President's Address in English]

Honourable Members,

It gives me great pleasure to welcome you to this first session of Parliament in 1987. I extend to you my best wishes for the successful completion of the budgetary and legislative business ahead.

2. In 1986 many of the gains made from the thorough and comprehensive policy changes initiated in several key areas were consolidated. At the same time it was a year in which the country was called upon to grapple with challenges, external as well as internal, to its unity and integrity. Our secular, democratic structure is boldly facing the forces of communalism and separatism. Nothing will ever shake the people of India from their adherence to the basic principles of democracy, secularism and socialism which form our Republic.

3. In Punjab the forces of democracy, unity, progress and secularism continue to be engaged in the struggle to isolate and wipe out the anti-national elements which are guided

and controlled by foreign sources. Under the leadership of the Chief Minister, Shri S. S. Barnala, the State Government and the people of Punjab, have shown exemplary courage in upholding the values of secular democracy. The people of Punjab have always been in the forefront to defend the unity and integrity of India. They played a historic role in the freedom struggle which has left the imperishable imprint of secularism and democracy on their mind and spirit. It is, therefore, not surprising that they have stood up to the blatantly unconstitutional effort to subvert the democratic process through a sinister exploitation of religious sentiments. In flagrant violation of the sacred tenets and traditions of the great religion founded by Guru Nanak, a small section has turned religious functionaries and holy shrines into instruments of terror and subversion. Today this is the central issue in Punjab. Government will not allow the enemies of India's unity and integrity to abuse and misuse religion for their nefarious ends of creating communal disharmony and of unleashing violence and hatred in Punjab. All patriotic, secular, democratic and progressive forces have to unite to build the strength of the people to overcome the reactionary, fascist and anti-national elements who are misguiding and confusing the masses in the name of religion. The challenge faces us all. No one can remain on the sidelines.

4. As the nation approaches the 40th anniversary of our freedom, it is fully conscious of the dangers posed by religious obscurantism and communalism. It was in April, 1948 that the Constituent Assembly (Legislative) passed a resolution calling upon Government to take steps to eliminate communalism from India's political life. The father of the Nation had been assassinated barely two months earlier. Memories of the ghastly killings were still fresh in the minds of our Constitution makers. The threat to the unity of India from

communalism loomed large before them. As we went ahead on our path of planned development, we began to assume that social and economic progress would automatically weaken the communal outlook. Experience has, however, shown that the communal and fundamentalist forces, aided and abetted by external elements, are challenging our basic values of nationalism, secularism, democracy and socialism. Indiraji's martyrdom was to defend the same sacred cause of the unity and integrity of India against the evil designs of communalists and reactionaries. These nefarious forces constitute a deeper malady which has persisted inspite of demonstrable progress in socio-economic sphere. The situation clearly calls for a reappraisal and Government propose a national dialogue for this purpose. Our precious heritage of unity in diversity can be preserved only by fighting all divisive forces.

5. There can be no better way of celebrating the 40th anniversary of freedom and the birth centenary of the architect of modern India, Jawaharlal Nehru, than concerted and resolute action to remove the cancerous cells of communalism from our body politic. The National Committee for these celebrations, headed by the Vice-President of India, will devise a comprehensive programme to inculcate secular values and scientific temper.

6. While the Government were engaged in controlling extremist activities in Punjab, a new danger appeared on our borders. In January, 1987, Pakistan deployed strike formations in a menacing posture threatening Punjab and Jammu & Kashmir. As Members are aware, our borders are largely manned by para-military forces. Faced with this situation, the Government had to deploy our armed forces for safeguarding the borders. Serious tension was generated by the forward movement of

Pakistani forces. The Prime Minister took the initiative for immediate talks between the two Governments. An agreement on measures to de-escalate the situation was reached during negotiations between the two Government held in Delhi recently and Pakistan agreed to withdraw their Army Reserve North from the Ravi-Chenab corridor. Further talks will be held in Islamabad. India's policy is based on peace and cooperation with all nations. Government have taken various measures to strengthen cooperation with our neighbours. While determined to preserve our sovereignty and integrity, India is prepared to remove all causes of tension and distrust between the two countries in the spirit of bilateral co-operation embodied in the Shimla Agreement.

7. The Mizoram Accord, signed in 1986, brought to an end decades of insurgency and strife in that beautiful part of our country. Pursuant to this Accord, Statehood has been conferred on Mizoram and elections have been held. A new Government has taken office.

8. The aspirations of the people of Arunachal Pradesh for a full-fledged State have been fulfilled by the enactment of parliamentary legislation to confer the Statehood on Arunachal Pradesh. The new State came into existence on February 20, 1987. A new chapter in the history of the people of Arunachal Pradesh has begun.

9. Government are committed to safeguarding the rights and interests of minorities. The solemn assurances contained in our Constitution regarding religious, cultural and linguistic matters have been and are being implemented in letter and spirit. Government have continued to carefully monitor the implementation of the 15-point programme formulated by Shrimati Indira Gandhi to ameliorate the condition of minorities.

10. In my Address on February 20, 1986 I had outlined the priority areas for 1986-87 and beyond. The main policy thrusts were:—

(i) Formulation of the revised 20-point programme;

(ii) Formulation of the new education policy;

(iii) Formulation of technology missions to improve the condition of the rural and urban poor;

(iv) A new orientation to our agricultural policy and taking the green revolution to the eastern region;

(v) A more effective strategy for family planning;

(vi) Intensification of industrial growth;

(vii) Promotion of exports and tourism;

(viii) Reforms in the administrative system; and

(ix) Changes in electoral laws.

11. My Government have taken action in all these areas and positive results are beginning to flow.

12. The 20-point programme of 1986 has sharpened the focus on measures to eradicate poverty. The main features of the restructured programme are:—

(i) Poverty alleviation programmes which aim at expansion of rural employment and improvement of productivity and production;

(ii) Programmes for ensuring justice to scheduled castes and scheduled tribes;

(iii) Reduction of income inequalities and removal of social and economic disparities;

(iv) strengthening of the movement to ensure equal status for women;

(v) Creation of new opportunities for youth;

(vi) Provision of safe drinking water for all villages;

(vii) Protection of environment;

(viii) Supply of energy for the villages; and

(ix) Evolving a more responsive administration.

13. The new education policy has been formulated. It is an effective instrument in our fight against poverty. Its major aim is to reach out to the poor and the deprived and to place in their hands the means to gain control over their own destiny. Programmes such as the Operation Blackboard, non-formal education, adult education, vocational education and Navodaya Vidyalays will bring about qualitative changes in education. They will directly help socially and economically backward sections of the community. The new policy will also strengthen national integration. We have emphasized the importance of spreading an awareness and involvement of all our people in the heritage of India. The newly established zonal cultural centres have begun undertaking this task with enthusiasm and have organised innovative Festivals of our culture in Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Meghalaya, Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Arunachal Pradesh and Mizoram and *Apna Utsav* in the capital.

14. Five technology missions have been set up in the following areas:—

(i) Drinking water for all villages;

(ii) Eradication of illiteracy;

(iii) Universal immunisation of children;

(iv) Production of oilseeds and manufacture of edible oils;

(v) Improved communications.

Government are considering issues relating to an effective management and monitoring system for the missions. The key idea here is to involve the people in activities relating to the missions so that they realise the potential for individual and social development.

15. The reorientation of agricultural policy has proceeded satisfactorily. Growth of productivity in the eastern region has vindicated Government strategy. To increase and stabilise production and productivity in the major part of our land resources, a national programme of rainfed agriculture through watershed development has been launched during the current year in 16 major rainfed/dry-land farming States. A National Pulses Development Project, with an outlay of Rs. 50 crores, has been started in 1986-87 to increase production of this essential protein crop.

16. We have formulated a new family planning strategy with major emphasis on voluntary acceptance of the two child norm. The programme will be integrated with health care, nutrition and education programmes. Government have decided that the leading role in promotion of the family welfare programme should be played by voluntary agencies.

17. In the sphere of industry, the dynamic thrust for efficiency and modernisation has begun to show results. Industrial production has picked up significantly.

18. Intensive efforts have been made on the basis of a coordinated approach to promote exports of both primary commodities and manufactured products. In our strategy manufacturing has been assigned the role of growth sector. A concessional rate of duty has been allowed on imports of modern capital goods for export production. Contemporary technology is being permitted for the thrust sectors. Significant fiscal and financial measures such as the new cash compensatory scheme, the duty drawback

system, availability of MODVAT in respect of 38 specified chapters, deduction in respect of profits for exports, sharp reduction in the rates of interest on pre-shipment and post-shipment credit for exports and the new computer software policy are intended to boost exports.

19. The process of reform in our administrative system has gathered momentum. There has been a positive response of the civil servants to the new imperatives of accountability, social responsibility and a new work ethic. Government are determined to carry forward the task of bringing about qualitative improvements in Government management with the cooperation of all sections of the work force.

20. The basic structure of our electoral system has stood the test of time. It has ensured free and fair elections to Parliament and State Legislatures and has been recognised and acclaimed as such by the whole world. Based on the report of the Chief Election Commissioner of 1986, Government have formulated certain suggestions, which are to be discussed with the various political parties and also thrown open to public debate. Necessary legislation will be initiated, as in the past, on the basis of consensus evolving from such discussions.

21. 1986 will be remembered for significant legislation affecting important areas of national life. Stringent and comprehensive environment protection legislation has been enacted. It was brought into force on November 19, 1986 as a fitting tribute to the memory of Shrimati Indira Gandhi who did more than anyone else to raise environmental consciousness.

—The rights of the consumers are now part of the statute book.

—Radical laws have been passed to improve the status of women.

—The Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 was amended to protect all persons sexually exploited for commercial purposes. Stricter punishment has been prescribed for living on the earnings of prostitution of children and minors.

—The Dowry Prohibition Act was amended, shifting the burden of providing that there was no demand for dowry on the person who takes or abets the taking of dowry. Offences under the Act have been made non-bailable.

—Indecent Representation of Women (Prohibition) Act has been passed under which depiction of figure of a woman, her form or body, which has the effect of being indecent, derogatory or which denigrates woman has been made punishable.

A significant feature of these laws is that legal remedy can be invoked by citizens. In implementing these far-reaching laws, the cooperation of public spirited and socially conscious citizens is of vital importance.

22. Let me now turn to the major trends in the economy.

23. Notwithstanding an indifferent monsoon the growth in gross national product in 1986-87 will be around 5 per cent. Thus the targeted growth rate of the Seventh Plan will be achieved for the second year in succession.

24. The foodgrain output will be somewhat higher than last year inspite of inadequate rains for the third year in succession. Government are concerned over the fact that even though agricultural production has reached higher levels, it is showing signs of levelling off. It is partly the result of three consecutive years of poor precipitation. The basic strategy for increasing agricultural production is sound. Vigorous implementation of projects and programmes for increasing irrigation potential and popularising the use of high-yielding varieties of seeds is expected

to achieve the targeted growth rates of the Seventh Plan. Government have taken major policy initiatives to increase the domestic production of oilseeds.

25. The industrial infrastructure has performed remarkably well both in 1985-86 and 1986-87. The average annual growth rates for the last two years are likely to be 9.5 per cent in power, 6 per cent in coal, 7.7 per cent in saleable steel, 6.8 per cent in hot metal, 8 per cent in railway freight and 16.5 per cent in fertilizers. The significant aspect of the infrastructural scene is that annual performance has continuously improved, extending over every quarter. In many cases, the lowest production in a quarter has been higher than the highest production recorded in any quarter of the preceding year. The infrastructure has begun to use investments in an efficient manner.

26. The revised index of industrial production (base 1980-81-100), with a wider and more representative coverage than the old index provides evidence of satisfactory industrial growth. In 1985-86 industrial production grew at the rate of 8.7 per cent. In 1986-87 growth rate is expected to be 7-8 per cent. There has been impressive growth in electronics during the previous two years at the rate of around 40 per cent per annum. The public sector has continued to play the key role in our economic development. At the end of 1985-86, the total investment in Central public enterprises stood at Rs. 50,341 crores, registering an increase of Rs. 14,947 crores compared with 1984-85. The financial performance of Central public enterprises has shown an encouraging trend. Measures have been taken to strengthen the autonomy of public enterprises and to make them accountable for results.

27. Public stocks of foodgrains have continued at high levels and stood at 23 million tonnes in December, 1986.

This has enabled Government to make additional allocations of rice and wheat to States for public distribution, to provide rice and wheat at concessional rates to integrated tribal development projects and nutrition programmes and to make higher allocations for the National Rural Employment Programme and the Rural Labour Employment Guarantee Programme. Comfortable stocks of foodgrains also enabled Government to give adequate quantities to drought-stricken States for the food-for-work programme.

28. There has been a major reorientation of policy to stimulate sugarcane and sugar production. The new two-year sugar policy aims at providing sugarcane farmers with more remunerative prices. It has also created a stable environment by announcement of the statutory minimum price a year in advance. As a result of this policy, sugar production increased by almost one million tonnes in 1985-86, and is expected to increase further in 1986-87. This has enabled Government to reduce sugar imports.

29. The technology mission for boosting oilseeds production has started functioning. A programme with an outlay of Rs. 170 crores during 1986-90 has been launched to increase production of oilseeds to 18 million tonnes in 1989-90. In Kharif 1986, productivity of oilseeds is estimated to have gone up by 10 per cent and production by 7 per cent over Kharif 1985, despite adverse weather conditions which reduced acreage by 3 per cent. Edible oil imports were reduced to provide an incentive to domestic production. In 1985-86 imports were reduced by 55 per cent in value terms and over 15 per cent in quantity terms. Fiscal incentives have been provided to ensure processing of greater quantities of minor oilseeds and rice bran into edible oils.

30. In 1986-87, anti-poverty programmes received stronger emphasis. The Integrated Rural Development

Programme (IRDP) and the Employment Programmes are the kingpin of the anti-poverty strategy. In 1986-87 an outlay of Rs. 543.83 crores was provided for the Integrated Rural Development Programme. This may be compared with Rs. 207.7 crores provided in 1984-85 and Rs. 205.9 crores in 1985-86. Upto the end of December 1986, 2.07 million families have been assisted. New features have been introduced in the implementation of the programme. They are higher level of investment per family, provision for forward and backward linkages, emphasis on training of beneficiaries, involvement of voluntary organisations, introduction of concurrent evaluation and increasing the assistance to women. Under all these programmes the basic thrust is to provide maximum assistance to the poorest of the poor and to scheduled castes and scheduled tribes.

31. The National Rural Employment Programme and the Rural Landless Employment Guarantee Programme were strengthened in 1986-87. Employment aggregating to 550 million mandays is expected to be created. There has been a noteworthy step up in outlays on NREP. In 1986-87 a total outlay of Rs. 479.75 crores was provided by the Centre compared with Rs. 230 crores for 1984-85 and Rs. 337.21 crores for 1985-86. Under RLEGP, which is wholly funded by the Centre, an outlay of Rs. 731.10 crores was provided for 1986-87 which may be compared with Rs. 400 crores for 1984-85 and Rs. 606.33 crores for 1985-86.

32. The 20-point programme of 1986 emphasises the provision of safe drinking water for all villages. In 1986-87, a total amount of Rs. 794.05 crores was allocated for the drinking water programme in Central and State plans taken together. 40,000 villages are expected to be covered exceeding the target of 35,930 villages. Special attention is being paid

to provision of water supply for scheduled castes and scheduled tribes.

33. In 1986-87, the outlay for the annual plan was stepped up substantially. For the first time in our planning history, 40 per cent of the Five Year Plan was financed in real terms in the first two years of the plan period. In allocation of resources high priority was accorded to anti-poverty programmes and to strengthening the core sectors of the economy. A massive increase of 60 per cent was made in the outlay for major anti-poverty programmes. The outlays for agriculture, rural development and irrigation were stepped up by nearly 30 per cent. The plan provision for education was increased by 60 per cent. The Central plan for 1986-87 envisaged an outlay of Rs. 22,300 crores, representing an increase of 20.5 per cent over the last year's outlay. The actual outlay of the plan is likely to be higher at around Rs. 23,000 crores. Nothing could illustrate better the strong commitment of Government to the pivotal role of planning in India's development.

34. Government have taken steps to implement the basic proposals outlined in the long term fiscal policy. The tax structure is being reformed and simplified, strong emphasis has been laid on mobilising resources for development by better administration and enforcement to improve compliance; a stable fiscal environment is being created to stimulate savings and investment, and a more open approach has been adopted in regard to fiscal policy.

35. Central Government revenues which increased by 23 per cent in 1985-86 have shown a further increase of over 17 per cent in April-December, 1986. Personal income-tax collection recorded an impressive growth of 30 per cent in 1985-86; they have grown by another 16 per cent in April-December, 1986. The continued buoyancy of Central revenues has

vindicated Government's fundamental approach of reasonable tax rates combined with strict enforcement of tax laws.

36. A Cabinet Committee on Exports was set up to expedite decision making on policies and programmes for promotion of exports. Exports grew by 17.3 per cent in April-November, 1986 over the corresponding period of last year. Imports increased by only 1.4 per cent over the same period. As a result the trade deficit has shown a substantial decline. We cannot, however, afford to be complacent. The challenge of self-reliance and of building a fully independent economy demands unremitting effort.

37. In the current year we crossed the one million mark in foreign tourist arrivals. Foreign exchange earnings from tourism are estimated at Rs. 1600 crores as compared to Rs. 1300 crores during 1985-86.

Domestic tourism is being given special importance to promote national integration. Central Government is providing assistance for wayside facilities, wildlife sanctuaries sound and light shows, and cheaper tourist accommodation.

38. While impressive results have been achieved in the matter of resource mobilisation, a similar effort has to be directed to controlling expenditure. The imperatives of growth with social justice compel serious attention to the task of containing unproductive expenditure.

39. The consumer price index gives cause for concern. However, inflation, as measured by the wholesale price index has been kept within reasonable limits. Government will continue to pursue policies to counteract inflationary trends in our economy.

40. During the last two years, a positive trend of improvement was seen in industrial relations. Strikes and lockouts declined from 2094 in 1984

to 1716 in 1985 and 1234 in 1986 (January to October). The loss of mandays due to industrial disputes fell from 56.03 million mandays in 1984 to 29.37 million mandays in 1985 and 19.41 million mandays during 1986 (January to October). Government have taken a number of steps to ensure that unorganised workers receive entitled benefits.

Industrial workers have made a notable contribution to raising production and productivity in the last two years. Government are committed to safeguarding their interest and to enlist their cooperation for accelerated industrial growth.

41. Government have continued to pursue our non-aligned foreign policy objectives of peace, disarmament, development and cooperation with all nations for building an equitable world order.

42. The Six Nation Five Continent initiative in which Argentina, Greece, India, Mexico, Sweden and Tanzania are taking part, has produced a favourable impact on public opinion throughout the world for intensive and sustained effort to bring about nuclear disarmament. At Reykjavik radical proposals for ending the nuclear arms race were placed on the table. It is unfortunate that no agreement was reached. We have continued to urge both the USA and the USSR to persevere in their efforts to fulfil the aspirations of humankind for peace and for a world free from nuclear weapons.

43. At the Non-aligned Summit at Harare, India handed over the chairmanship of the movement to Zimbabwe. The Summit acclaimed the role our country has played in strengthening non-alignment and in reaffirming the basic objectives of the Movement. The Summit entrusted to our Prime Minister the chairmanship of the newly established AFRICA Fund Committee to carry forward the struggle against apartheid and to support the efforts of the Frontline States. The AFRICA

Fund Summit held in Delhi on January 24-25, 1987 has given concrete shape to the concept articulated at Harare. Government are convinced that comprehensive mandatory sanctions alone will compel the racist regime in South Africa to forestall blood-shed and listen to the voice of reasons. Governments that are in a position to influence South Africa, because of their commercial and economic relations, have to mount pressure through comprehensive mandatory sanctions.

44. India's policy of expanding co-operation in our region has achieved significant results. The successful SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) Summit held in Bangalore in November, 1986 under India's chairmanship has demonstrated the benefits of regional co-operation. A permanent Secretariat of SAARC has since been established in Kathmandu. New areas including control of drug trafficking, children's welfare, broadcasting, tourism and scholarships have been identified for the programme of SAARC co-operation. Our Prime Minister took the opportunity of SAARC meeting to hold useful bilateral discussions.

45. Despite the set-back caused by the deployment by Pakistan of its troops on our borders, efforts are continuing to create a basis for co-operation with Pakistan. The main hurdles in the way of normalisation are Pakistan's clandestine effort to acquire nuclear weapons capability, its arms programme with serious implications for our security environment and its support to anti-national and secessionist elements in Punjab.

46. It is unfortunate that the promise held out by our bilateral discussions with Sri Lanka at Bangalore and of subsequent high level consultations in December, 1986 has received a set-back. The negotiating process has been hindered by the hesitations of the Government of Sri Lanka in regard to their own formula of December 19, 1986. The massive military

operations undertaken by the Sri Lanka security forces and the economic blockade of Jaffna area have created further complications. We are deeply affected by the hardship, suffering and loss of life of the Tamil civilian population of Sri Lanka. The ethnic issue in Sri Lanka can only be resolved through political dialogue.

47. My Government continues to strive for a just and peaceful settlement of the border question with China. The question remains crucial to full normalisation of our relations. The unfortunate development on the border continues to cause concern. Our position on the border question is well known. We are in discussion with China on the issue.

48. We uphold the unalienable rights of the Palestinian people. We support the liberation struggle of the peoples of Southern Africa. We have repeatedly urged an early end to the fratricidal war between Iraq and Iran. We continue to support the efforts of the Contadora group to achieve a peaceful and lasting settlement of the crisis in Central America. We have also supported the UN Secretary General's initiative on Afghanistan. We welcome the flexible responses to the outstanding issues in regard to Afghanistan and trust that conditions will be created soon to ensure the status of Afghanistan as an independent, non-aligned country free from outside interference and intervention.

49. During the last year, I paid goodwill visits to Nepal, Greece, Poland and Yugoslavia. The Vice-President visited France and Botswana. The Prime Minister paid bilateral visits to the Maldives, Zambia, Zimbabwe, Angola, Tanzania, Mauritius, Mexico, Indonesia, Australia, New Zealand and Thailand. The Prime Minister also participated in the Commonwealth Heads of Government Review Meeting in London, the Summit Meeting of the Six Nation Five Continent Peace Initiative at Ixtapa and

the Eighth Non-aligned Summit in Harare, besides visiting Sweden to attend the funeral of late Prime Minister Olof Palme.

50. We had the privilege to host the Prime Minister of Greece, the Prime Minister of the Republic of Korea, the Prime Minister of Turkey, the President of Seychelles, the Chancellor of the Federal Republic of Germany, the President of the African National Congress, the President of SWAPO, the President of Bangladesh, the Prime Minister of Yugoslavia, the President of Nicaragua, the Prime Minister of Zambia, the King of Jordan, the Prime Minister of Denmark, the President of Peru, the Prime Minister of Malaysia and the President of Finland. The then Prime Minister and the current President of People's Democratic Republic of Yemen and the Prime Minister of Italy made transit visits to India. President Zia-ul-Haq of Pakistan paid an unofficial visit.

51. These bilateral visits have strengthened our friendly relations with these countries. A large number of agreements have been signed to further bilateral cooperation in economic commercial, scientific and cultural fields.

52. In the context of the close and friendly relations that have characterised the four decade history of Indo-Soviet cooperation, the visit of Mr. Gorbachev, the General Secretary of CPSU, was a landmark. The Delhi Declaration signed by Mr. Gorbachev and our Prime Minister has provided a qualitatively new framework for international relations based on non-violence, justice and equality. It will have worldwide significance in establishing new attitudes and values relevant to the crucial problems of humanity.

53. The thrust of Government policy is to improve the welfare of economically and socially weaker sec-

tions of the community. The primary focus of policies and programmes initiated during the last two years has been to assist the landless agricultural labour, the small and marginal farmers, artisans and craftsmen, handloom weavers, women, children; the urban poor, scheduled castes and scheduled tribes and other backward classes. Our strategy of development will continue to strongly emphasize social justice as its foremost objective.

54. In spite of the many difficult problems we are facing, the people have high confidence in their capacity to build a strong and prosperous India. This confidence comes from our impressive achievements. India stands as a symbol of stability and progress. Our commitment to basic values and our determination to preserve our cultural heritage have enabled us to march forward with our head held high. We still have much to do. With the cooperation and unbounded enthusiasm of our people, my Government will take the country forward on its chosen path.

55. Our tasks are anchored to basic national priorities. National cohesion will be strengthened. Communalism will be fought tooth and nail. The anti-poverty programme will be implemented with vigour. The core sectors of our economy will be strengthened and expanded to ensure self-reliant growth. The energy and vitality of our youth will be harnessed to nation building. The spirit of sacrifice which permeated the struggle for freedom must be recaptured to face the challenges that confront us. A passion for nation building must fill our hearts. For the accomplishment of these momentous tasks, I give you my good wishes.

Jai Hind.